आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 06.09.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
- सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता व दुग्ध विकास विभाग की बैठक ली। साइलेज का उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण को लेकर विभागों को आपसी समन्वय बना कर कार्य करने निर्देश दिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत तैयार राज्य पाठ्यचर्या को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ने सर्वसम्मति से पारित किया।
- पौड़ी जिले की सभी तहसीलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर औचक निरीक्षण कर नमक के सैंपल लिए गए।

नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद से परीक्षा का एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है और योग्य युवाओं को लगातार अवसर मिल रहे हैं।

दुग्ध विकास बैठक

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज देहरादून में दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में सहकारिता व दुग्ध विकास विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में प्रदेशभर के पशुपालकों व गौपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए साइलेज के उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण पर विस्तार से चर्चा की गई। सहकारिता मंत्री ने दोनों विभागों को आपसी समन्वय बना कर कार्य करने निर्देश दिए, ताकि प्रदेशभर के पशुपालकों, गौपालकों को रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता का साइलेज उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों और दुग्ध उत्पादकों की समृद्धि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक टीवी चैनल से साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि चाहे रूसी तेल हो या कुछ और, दरों और लॉजिस्टिक्स के मामले में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेंगे। श्रीमती सीतारामन ने दोहराया कि भारत के आयात बिल में कच्चे तेल का योगदान सबसे ज्यादा है।

हरिद्वार नगर निगम

हरिद्वार नगर निगम ने सड़कों पर लगे खंबों पर फैले विभिन्न विभागों और कंपनियों के तारों को हटाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में निगम ने कार्रवाई शुरू करते हुए शिवमूर्ति चौक से रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक स्ट्रीट लाइट पोलों पर बिना अनुमति लगाए गए फाइबर के तारों को हटाया। अवैध रूप से लगाए गए इन केबलों से न केवल बिजली व्यवस्था बाधित हो रही थी, बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी। गौरतलब है कि निगम ने सभी विभागों को पहली सितंबर से पहले अपने–अपने तार हटाने की चेतावनी दी थी। नगर निगम ने भविष्य में किसी भी प्रकार के तार, केबल या अन्य उपकरण निगम की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगाने की चेतावनी दी है। साथ ही केबल ऑपरेटरों या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा स्ट्रीट लाइट पोलों पर अव्यवस्थित रूप से लगाए गए तारों को तत्काल हटाने को कहा है। ऐसा न करने पर निगम इन तारों को स्वयं हटा देगा।

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों के तहत तैयार राज्य पाठ्यचर्या को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत अब प्रदेशभर के विद्यालयों में 240 दिन अनिवार्य रूप से कक्षाओं का संचालन किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक सप्ताह 32 घंटे का शैक्षणिक दिवस आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा व मूल्यांकन कार्य के लिए 20 दिन और सह–शैक्षणिक गतिविधियों व बस्ता रहित दिवसों के तौर पर 10 दिन तय किये गये हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब स्कूलों में बच्चों को तीन भाषाओं– अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में पढ़ने का अवसर मिलेगा।

नमक सैंपल

पौड़ी में राजस्व विभाग, पूर्ति विभाग और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले की सभी तहसीलों की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सस्ते गल्ले की दुकानों से दिए जाने वाले नमक की गुणवत्ता जांची गई। दुकानों में रखे नमक के पैकेटों की सैंपलिंग की गई, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों और उप निरीक्षकों ने दुकानों में अन्य खाद्यान्न सामग्रियों की उपलब्धता और गुणवत्ता का भी परीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नमक की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक एहतियात बरती जाए। उन्होंने नमक के रख–रखाव और उचित हैंडलिंग के संबंध में भी निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं तक केवल उच्च गुणवत्ता वाले आयोडाइज्ड नमक ही पहुंचेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है।

नशामुक्त अभियान बैठक

चम्पावत जिले में नशा मुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नशे को समाप्त करने के लिए प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठनों को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, छात्रों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने और नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम जैसी अन्य गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को नशाखोरी और अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शिक्षण संस्थानों की 100 गज की परिधि में पीली मार्किंग की जाए। इस परिधि के भीतर तम्बाकू और धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसका उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक भागीदारी से ही नशा मुक्त समाज का निर्माण संभव है। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।